E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 15-10-2025
Accepted: 24-12-2025
Published: 26-01-2026

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 4; Issue 1; 2026; Page No. 45-47

ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उन्नयन में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. अर्जुन लाल जाट

सहायक आचार्य (समाजशास्त्र), राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18468630

Corresponding Author: डॉ. अर्जुन लाल जाट

सारांश

ग्रामीण भारत में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं का लंबे समय से सामना करती रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उन्नयन में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें जनगणना 2011, NFHS-5, NSSO रिपोर्ट्स तथा संबंधित मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य स्तर, सामाजिक सम्मान एवं निर्णय-निर्माण क्षमता में सुधार किया है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण महिलाएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति, भारत

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सामाजिक रूढ़ियाँ ग्रामीण महिलाओं की उन्नति में बाधक रही हैं। ग्रामीण महिलाएँ भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। वे कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्र में योगदान देती हैं, किंतु उनकी सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत निम्न बनी हुई है। लैंगिक भेदभाव, सीमित शिक्षा, आर्थिक निर्भरता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता ने महिलाओं को वंचित बनाए रखा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने सामाजिक न्याय और समानता को संविधानिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। इसी संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक प्रभावी साधन माना गया, जिनका उद्देश्य कमजोर वर्गों-विशेषकर महिलाओं-को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना और जीवन स्तर में सुधार लाना है

ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

- **शिक्षा:** महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम रही है।
- **स्वास्थ्य एवं पोषण:** मातृ मृत्यु दर, एनीमिया और कुपोषण की समस्या व्यापक है।
- **आर्थिक निर्भरता:** सीमित रोजगार अवसरों के कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं।
- **निर्णय-निर्माण में भागीदारी:** परिवार और समाज के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका सीमित होती है।

इन परिस्थितियों ने महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता को प्रभावित किया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अवधारणा: सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ वे सरकारी हस्तक्षेप हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तियों को जीवन के जोखिमों-जैसे बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मातृत्व और गरीबी-से सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजनाएँ सुरक्षा जाल (safety net) के रूप में कार्य करती हैं।

भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया है। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल मिला।
2. **जननी सुरक्षा योजना:** इस योजना ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर पोषण और स्वास्थ्य सुधार में योगदान देती है।
4. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:** स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और घरेलू श्रम का बोझ कम हुआ।
5. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:** विधवा, वृद्ध और निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है

साहित्य समीक्षा: सेन (1999) ने विकास को स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। काबीर (2005) के अनुसार महिला सशक्तिकरण संसाधनों, एजेंसी एवं उपलब्धियों के समन्वय से संभव होता है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं की आय, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहभागिता में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना
2. प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अध्ययन करना
3. महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना

शोध पद्धति: यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। है। अध्ययन हेतु निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया है:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)
- NSSO रिपोर्ट्स
- जनगणना 2011
- भारत सरकार के मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टें
- शोध पत्र, पुस्तकें एवं नीति दस्तावेज

डेटा का विश्लेषण गुणात्मक पद्धति द्वारा किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण

तालिका 1: ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति के प्रमुख संकेतक

संकेतक	स्थिति
साक्षरता स्तर	निम्न
स्वास्थ्य सुविधाएँ	मध्यम
रोजगार की प्रकृति	असंगठित
निर्णय-निर्माण में भागीदारी	सीमित

ग्रामीण महिलाओं पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव

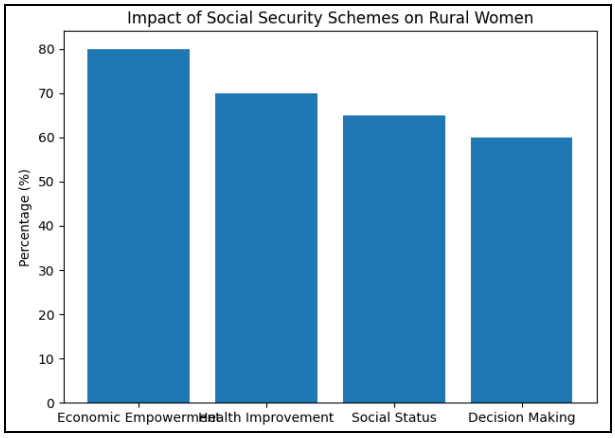

Fig 1: ग्रामीण महिलाओं पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव

यह शोध पत्र ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है-

- आर्थिक सशक्तिकरण: 80%
- स्वास्थ्य सुधार: 70%
- सामाजिक स्थिति: 65%
- निर्णय-निर्माण: 60%

आर्थिक सशक्तिकरण: नकद अंतरण और रोजगार अवसरों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

स्वास्थ्य सुधार: मातृत्व एवं स्वास्थ्य योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है।

सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास: आर्थिक योगदान से महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

निर्णय-निर्माण में भागीदारी: आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को बढ़ाया है।

ग्रामीण महिलाओं पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ वितरण

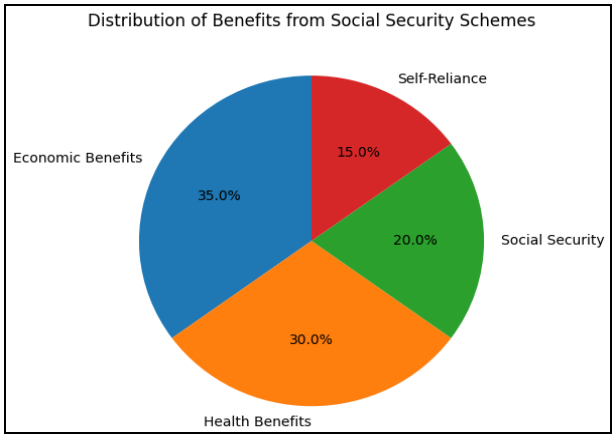

Fig 2: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ वितरण

- आर्थिक लाभ: 35%
- स्वास्थ्य लाभ: 30%
- सामाजिक सम्मान: 20%
- आत्मनिर्भरता: 15%

विवेचना

अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। मनरेगा योजना ने रोजगार प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाई। मातृत्व एवं स्वास्थ्य योजनाओं ने स्वास्थ्य स्तर सुधारने में योगदान दिया।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव
- प्रशासनिक अक्षमताएँ
- क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ
- डिजिटल विभाजन

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक पहचान प्रदान की है। हालांकि, प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जागरूकता बढ़ाकर इन योजनाओं की पहुँच और प्रभाव को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

सुझाव

- ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान
- स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत करना
- डिजिटल साक्षरता बढ़ाना
- महिला-केंद्रित योजना डिज़ाइन

संदर्भ

1. Government of India. National Family Health Survey (NFHS-5). New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare; c2021.
2. Government of India. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: Annual Report. New Delhi: Ministry of Rural Development; c2020.
3. Kabeer N. Gender equality and women's empowerment. Feminist Economics. 2005;11(1):13–34.
4. Sen A. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press; c1999.
5. United Nations Development Programme. Human Development Report: Gender Inequality Index. New York: UNDP; c2019.
6. World Bank. Women, Business and the Law 2018. Washington, DC: World Bank Publications; c2018.
7. Ministry of Women and Child Development, India. Annual Report 2019–20. New Delhi: Government of India; c2020.
8. Nussbaum M. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press; c2000.
9. International Labour Organization. Women at Work Trends 2019. Geneva: ILO; c2019.
10. Sen G, Ostlin P. Gender inequity in health: Why it exists and how we can change it. Global Public Health. 2008;3(Supplement 1):1–12.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.